uncovered villages and GPs of the State. Recently, the Union Home Ministry has sanctioned about 488 mobile base stations which mean we need 2,000 additional mobile base stations to cover all the villages and GPs of the State.The telecom service providers, however, are unwilling to put up the requisite infrastructure in all the villages of the KBK Districts which are largely tribal-dominated and LWE-affected.

Sir, I will give an example. On 28th July, 2020, BSNL came up with a notification to discontinue its 4G infrastructure services from Kalahandi citing revenue losses and commercial non-viability. In this very august House, I strongly objected to this notification of BSNL and thanks to you and the Government, the notification has been withdrawn. All of us know that poor internet connectivity affects all the Government schemes and, largely, the education sector is hugely affected because of this, particularly, in a year when we are rolling out the NEP and, particularly, when the Covid pandemic has hit the education sector so badly and children have to depend on online education. How will the tribal children of KBK Districts and, generally, across the country, continue their education if this kind of attitude by the telecom service providers continue?

श्री मुजीबुल्ला खान (ओडिशा) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

DR. SONAL MANSINGH (Nominated): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

Need for issuance of monographs by Publications Division and National Book Trust on authors, journalists, newspapers and magazines on 75th year of Independence

श्री सभापति : श्री राकेश सिन्हा, आप बोलिए।

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित) : सभापति महोदय, महोदय, हम अगले साल आज़ादी का 'अमृत महोत्सव' मनाने जा रहे हैं। साधारणतया जब स्वतंत्रता की बात आती है तो हमारा ध्यान राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर ही केंद्रित होता है, लेकिन साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन को वैचारिक आधार और मानसिक ताकत देने का काम कई पत्र-पत्रिकाओं, लेखकों और

साहित्यकारों ने किया है, जिनका त्याग किसी भी राजनीतिक कैदी से, राजनीतिक कार्यकर्ता से कम नहीं था। चाहे वह टी.प्रकाशन का 'स्वराज्य' हो या नागेश्वर राव पंतुलू की 'आंध्र पत्रिका' हो, सच्चिदानंद सिन्हा का 'हिन्दुस्तान रिव्यू' हो या महाराष्ट्र से मराठी में प्रकाशित होने वाले 'काल', 'केसरी', 'स्वतंत्र', 'ज्ञान प्रकाश' हों। इस तरह के पत्र-पत्रिकाओं ने उस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया था। मैं इस सदन के सामने दो घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। एक 'हिंदी प्रदीप' नामक अखबार था..(**व्यवधान**)..

MR. CHAIRMAN: Wahab*ji*, you are not supposed to come to this side. ...(*Interruptions*)... Whichever, but be on one side.

श्री राकेश सिन्हा: जो 1877 से लेकर 1910 तक तेईस वर्षों में 'हिंदी प्रदीप' को दस बार प्रिंटिंग प्रैस बदलनी पड़ी थी। ठीक उसी प्रकार पं. सुंदरलाल की प्रेरणा से प्रकाशित 'स्वराज्य', जो इलाहाबाद से प्रकाशित होता था, उसने एक विज्ञापन दिया था। सभापति महोदय, वह विज्ञापन संपादक के लिए था। उसमें जो लिखा गया था, वह इस प्रकार था - सेवा शर्तें - दो सूखी रोटियां, एक गिलास ठंडा पानी और प्रत्येक संपादकीय के लिए दस साल की सज़ा। मैं आपके माध्यम से सदन से अपील करना चाहता हूं कि आज़ादी के इस 'अमृत महोत्सव' पर हम ऐसे साहित्यकारों, पत्रकारों, पत्र-पत्रिकाओं को भी शामिल करें और उन्हें वही स्थान दें, जो राजनीतिक कार्यकर्ताओं को मिलता है। इस आंदोलन में एनी बेसेंट के 'न्यू इंडिया' ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, डा. हेडगेवार 'स्वातंत्र्य' पत्र निकालते थे और उस 'स्वातंत्र्य' अखबार को सिर्फ नौ महीने में सरकारी दमन के कारण बंद करना पड़ा था। ठीक उसी प्रकार बाल गंगाधर तिलक 'केसरी' अखबार निकालते थे। यद्यपि बाल गंगाधर तिलक एक राजनीतिक कार्यकर्ता भी थे, अतः उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा था। बालमुकुंद गुप्त, बाबूराव पराड़कर, बनारसीदास गुप्त, टी. प्रकाशन आदि जैसे लोगों पर प्रकाशन विभाग और नेशनल बुक ट्रस्ट को मोनोग्राफ प्रकाशित करना चाहिए। ऐसे पत्र-पत्रिकाओं के बारे में और जिन लोगों ने युगांतर में एक बड़ी भूमिका निभाई, उन सबके बारे में बताने के लिए हम एक छोटा म्यूज़ियम बना सकते हैं, जो कि आने वाली पीढ़ी को आज़ादी के आंदोलन में, स्वाधीनता प्राप्त करने में इन पत्र-पत्रिकाओं, साहित्यकारों और पत्रकारों की भूमिका को बता सके। सभापति जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश) : महोदय, मैं स्वयं को इस विषय के साथ संबद्ध करता हूं।

DR. FAUZIA KHAN (Maharashtra): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

SHRI K.C. RAMAMURTHY (Karnataka): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I would also like to associate myself with the Zero Hour mention made by the hon. Member.

श्री सभापति : धन्यवाद राकेश सिन्हा जी। श्री सैयद जफर इस्लाम, आप बोलिए।

Need for enrolment of more economically weaker persons under the *Ayushman Bharat Yojana*

SHRI SYED ZAFAR ISLAM (Uttar Pradesh): Mr. Chairman, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak on a very important issue. महोदय, मैं आज आपकी अनुमति से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम है, 'आयुष्मान भारत', मैं सदन में उस पर कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

महोदय, 'आयुष्मान भारत' स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है, वह सबको मालूम है। इसमें गरीब परिवारों के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है। जो 10.74 करोड़ फैमिलीज़ हैं, उनमें से 50 करोड़ लोगों को इंश्योरेंस कवर दे रहे हैं। यह बहुत ही सक्सेसफुल और दुनिया की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवर स्कीम है। It has become a template for many countries to follow. It has become a case study for many institutions where it is being discussed. Such a wonderful scheme has been designed by the Government of India. सरकार ने इसे डिज़ाइन किया है और उसका एक क्राइटीरिया दिया है। उस क्राइटीरिया में उन लोगों को इस फेहरिस्त में, लिस्ट में, चांस मिला है, जिनकी आबादी 40 प्रतिशत के करीब है। उसका क्राइटीरिया deprivation or occupational criteria, as per Census 2011 का है। ऐसी बहुत सी चीजें देखी गई हैं, जिनमें बहुत से लोग अभी ट्रेस नहीं हो पा रहे हैं। वे 2011 से गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं, लेकिन उनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। इस स्कीम को जिस तरह से डिजाइन किया गया है sustainable development and growth और उसका objective है, सरकार की जो मंशा है, that no one should be left behind, उस spirit को देखते हुए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी स्कीम है, जिसके माध्यम से सरकार ने करीब 3 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है। इसे दुनिया भी मानती है कि यह सबसे अच्छी स्कीम है और वह आश्चर्य करती है कि कैसे इतनी अच्छी स्कीम launch की गई। हम 'आज़ादी का अमृत महोत्सव' मनाने जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार और उनके सदस्य इस फेहरिस्त में नहीं हैं। वे या तो 2011 बाद या तो ट्रेस नहीं हो पा रहे या बहुत गरीब हो गए हैं। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि District Magistrate को यह अनुमति या निदेश दिया जाए कि ऐसे लोग जो genuinely गरीब हैं, उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल करके इसका फायदा पहुंचाया जाए।

SHRI SUJEET KUMAR (Odisha): Sir, I associate myself with the issue raised by the hon. Member.